



वायु प्रदूषण पर संसद में राहुल गांधी ने सरकार- कोई भी जबरन वज्रफ संपज्ञियों पर विपक्ष की संयुक्त कार्रवाई की जताई इच्छा कज़्जा नहीं कर सकता-ममता बनर्जी

नयी दिल्ली ११/०१ (संवाददाता):संसद में वायु प्रदूषण पर एक गंभीर और सीधे मुद्दे की बातचीत शुरू हुई है, जिसमें विपक्ष और सरकार पहली बार बिना टकराव के आगे बढ़ने की इच्छा दिखाते नजर आए हैं। मौजूद जानकारी के अनुसार, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता पर तात्कालिक और सर्वदलीय चर्चा की मांग करते हुए कहा कि यह ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति नहीं, बल्कि साझा प्रयासों की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के कई बड़े शहरों में लोग जहरीली हवा की चादर के नीचे जीवन बिताने को मजबूर हैं। उन्होंने चिंता जताई कि लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारियों से जूझ रहे हैं, बुजुर्ग सांस लेने तक में संघर्ष कर रहे हैं और कैंसर जैसे मामलों में भी



बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राहुल ने कहा कि यह वैचारिक मतभेदों का विषय नहीं है, बल्कि वह मुद्दा है जिस पर सच्चा और विपक्ष दोनों की सहमति बन सकती है। उनका कहना था कि यह चर्चा इस आधार पर होनी चाहिए कि भविष्य में देश को बचाने के लिए हम मिलकर ज़्या कदम उठा सकते हैं, न कि एक-दूसरे पर आरोप लगाने पर।

बता दें कि संसदीय कार्य

मंत्री किरन रिजिजू ने सरकार की ओर से इस चर्चा के लिए तत्परता जताई और कहा कि लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इस पर समय तय कर सकती है। गौरतलब है कि यह पहली बार है जब वायु प्रदूषण को लेकर संसद के भीतर दोनों पक्षों में एक सकारात्मक माहौल दिखाई दिया है। इसके बाद राहुल गांधी ने एज्स पर एक पोस्ट में वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय आपदा बताते

हुए कहा कि इसे तत्काल, व्यापक और ठोस राष्ट्रीय कार्ययोजना को आवश्यकता है। उन्होंने लिखा कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारी है और वे प्रधानमंत्री के साथ मिलकर इस दिशा में काम करने के लिए तैयार हैं।

वहीं वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा ने भी राहुल के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि यह समस्या बहुत लंबे समय से बढ़ रही है और अब सभी दलों को मिलकर एक एजशन प्लान तैयार करना चाहिए इस बीच, बता दें कि विश्व बैंक ने हाल ही में उज्जर प्रदेश और हरियाणा में स्वच्छ हवा से जुड़े दो बड़े कार्यक्रमों के लिए लगभग 600 मिलियन डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है। विश्व बैंक इंडिया के कार्यकारी निदेशक पॉल फ्रूसी ने कहा कि दक्षिण एशिया में

वायु प्रदूषण स्वास्थ्य, उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता पर गंभीर असर डाल रहा है, और ये कार्यक्रम न सिर्फ वायु गुणवत्ता में सुधार करेंगे बल्कि युवाओं और महिलाओं के लिए हरित नौकरियों के अवसर भी तैयार करेंगे। इधर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। शुक्रवार को शहर के ऊपर घना स्मॉग छाया रहा और एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 332 हो गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। दिल्ली के 30 से अधिक मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' दर्ज की गई, जबकिजहांगीरपुरी में एज्युआई 405 तक पहुंच गया जो 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है। राजधानी में लगातार बिगड़ती हवा लोगों के स्वास्थ्य, आवाजाही और रोजमर्रा ज़िंदगी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है।

राष्ट्रगान के अनादर को लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ याचिका दायर

पटना ११/०१ (संवाददाता): बिहार के मुजफ्फ़पुर की एक अदालत में शुक्रवार को एक याचिका दायर की गई जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पटना में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान का ध्वन्यांतरण करने का आरोप लगाया गया है। याचिका एक स्थानीय वकील सूरज कुमार ने मुजफ्फ़पुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ;पश्चिममध्य की अदालत में दायर की है। वकील ने याचिका दायर करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा ष्म्यमंत्रि ने बृहस्पतिवार को एक खेल आयोजन के उद्घाटन के दौरान अपने आचरण से राज्य की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया। अदालत से पुलिस को मुख्यमंत्री के खिलाफबीएनएस और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। उन्होंने बताया कि अदालत ने मामले की सुनवाई 25 मार्च को करना निर्धारित किया है। याचिका एक स्थानीय वकील सूरज कुमार ने मुजफ्फ़पुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ;पश्चिममध्य की अदालत में दायर की है।

सुर्वेदु अधिकारी

आग्रह किया। उन्होंने कहाए प्बंगाल को बचाना चाहिए। हिंदुत्व पर हमला हो रहा है और सभी को एक साथ आना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इस साल राम नवमी के दौरान बड़े पैमाने पर जशन मनाया जाएगा। पिछले सप्ताह कहा था कि छह अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर राज्य भर में 20ए000 से अधिक शोभायात्राएं निकाली जाएंगी। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों की तरहए पिछली दुर्गा पूजा के दौरान राज्य में हिंदू समुदाय के कई पूजा स्थलों में तोड़फोड़ की गई थी।

कोलकाता ११/०१ (संवाददाता):पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वज्रफ संपज्ञियों को मौजूदा नियमों के तहत सत्ता से संरक्षित किया जाएगा और कोई भी उन्हें जबरन अधिग्रहित नहीं कर सकता है। नदिया के कृष्णानगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए कई कल्याणकारी उपाय किए हैं, जिनमें 10,000 कब्रिस्तानों का निर्माण और ओबीसी आरक्षण लाभों का विस्तार शामिल है।

उन्होंने कहा, हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि वज्रफ संपज्ञि में नियमों का पालन होगा। अब मुतवल्ली (मस्जिद के न्यासी) इसका पालन करेंगे। हम किसी को भी वज्रफ संपज्ञि हासिल करने की अनुमति नहीं देंगे। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि चुनाव में मुस्लिम समुदाय से भारी समर्थन हासिल करने के बावजूद मुख्यमंत्री ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने दावा किया, जिसे 2021 में 92



प्रतिशत और 2024 में 91 प्रतिशत मुस्लिम वोट मिले थे, उसने अब वज्रफ के मुद्दे पर समुदाय को गड्डे में धकेल दिया है। अधिकारी ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने वज्रफ की कई एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है, यही वजह है कि सरकार केंद्र के 'उज्मीद' पोर्टल पर संपज्ञि के आंकड़े अपलोड करने की प्रक्रिया में देरी कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां अन्य राज्यों ने वज्रफ संपज्ञि के विवरण तुरंत अपलोड कर दिए हैं, वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की उदासीनता के कारण लगभग 80,000 संपज्ञियां लंबित पड़ी हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 27

अक्टूबर, 18 नवंबर और चार दिसंबर को तीन पत्र भेजे गए थे। इसके बाद ही मुख्यमंत्री के सचिव पी.बी. सलीम जागे और उन्होंने जिला मजिस्ट्रेटों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान ने टीएमसी के दोहरे मापदंड को उजागर किया है। कबीर ने कहा, पहले उन्होंने कहा था कि वे वज्रफ संशोधन अधिनियम लागू नहीं करेंगी, लेकिन फिर उनकी सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया। और अब वे जनता को गुमराह करने के लिए फिर से भ्रामक बयान दे रही हैं। टीएमसी सिर्फ वोटों के लिए इस समुदाय का इस्तेमाल कर रही है।

रान्या राव के अपमानजनक कवरेज से मीडिया को रोका जाए - कर्नाटक उच्च न्यायालय

बेंगलुरु ११/०१ (संवाददाता): कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह अभिनेत्री हर्षवर्दिनी रान्या और उनके पिता केप्राेमचंद्र राव के खिलाफ झूठी और अपमानजनक सामग्री प्रसारित या प्रकाशित करने से मीडिया संस्थानों को रोकने के लिए उचित कदम उठाए।

यह आदेश सोने की तस्करी के एक मामले से संबंधित चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच आया है जिसमें अभिनेत्री को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में रखा गया है। यह मामला दुबई से आने पर तीन मार्च को बेंगलुरु के केस्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रान्या राव के पास से कथित तौर पर 12.56 करोड़ रुपये की सोने की छड़ें जप्त किए जाने से जुड़ा हुआ है।

बीजापुर में एक इनामी समेत पांच नज़सली गिरफ्तार

बीजापुर ११/०१ (संवाददाता):छत्तीसगढ़ के नज़सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों ने एक इनामी समेत पांच नज़सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के उस्ूर थाना क्षेत्र में मारुड़बाका गांव के जंगल में सुरक्षाबलों ने पांच नज़सलियों ..नारायण भण्डारी ;45इए धरमा काका ;21इए नीला काका ;25इए किस्टा धरवा ;30इ और रामबाबू पुतेम ;26इ को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि नज़सली नारायण मारुड़बाका दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संगठन का अध्यक्ष है

तथा उसके सर पर एक लाख रूपए का इनाम था। पुलिस अधिकारियों ने बताया



इसके बाद रान्या के आवास की तलाशी में कथित तौर पर 2006 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2067 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद हुई थी। रान्या राव की मां एचण्पीण् रोहिणी ने 12 मार्च को एक दीवानी अदालतका रुख किया थाए जिसने बाद में एकपक्षीय आदेश जारी कर मीडिया को दो जून तक अभिनेत्री के खिलाफ कोई भी बयान देने से रोक दिया था।

बाद में रान्या के पिता की ओर से दायर याचिका के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा भी इसी प्रकार का निर्देश जारी किया गया था। हालांकिए रान्या के परिवार का कहना है कि कुछ मीडिया संस्थान ने इन न्यायिक निर्देशों के बावजूद सनसनीखेज और नुकसानदायक सामग्री प्रकाशित करना जारी रखा है। इस मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल को निर्धारित की गई है।



कि जिले में चल रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत सोमवार को उस्ूर थाने से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जिला

पुलिस बल के संयुक्त दल को नेलाकांकेरए मारुड़बाका और कमलापुर गांव की ओर रवाना किया गया था।

विरोध, विरोध, विरोध और समर्थन... कैसे हुआ ये? आलोचक ही बनते जा रहे फैन, अब पीएम मोदी को ढूंढने होंगे नए क्रिटिक

नयी दिल्ली ११/०१ (संवाददाता): महात्मा गांधी ने कहा था कि पहले वे आपको अनदेखा करते हैं फिर वे आप पर हंसते हैं फिर वे आपसे लड़ते हैं और फिर आप जीत जाते हैं। सालों से पीएम मोदी के कट्टर आलोचकों ने उनकी हर नीति की आलोचना कीए उन्हें भला बुरा कहा और उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और उनके कट्टर आलोचक उनकी तारीफ कर रहे हैं। पीएम मोदी को नए नफ़रत करने वालों की ज़रूरत पड़ने वाली है। आइए देखें कि कैसे पीएम मोदी के कट्टर आलोचक उनके सबसे बड़े प्रशंसक बन गए हैं। दिल्ली में एक परिचर्चा के दौरान रूस.यूक्रेन युद्ध और भारत की कूटनीति पर टिप्पणी करते हुए शशि थरूर ने कहा कि मुझे यह स्वीकार करना होगा कि 2022 में रूस.यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख की आलोचना करने पर मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मोदी ने दो हफ्तों के अंतराल में यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति दोनों को गले लगाया और दोनों जगह उन्हें स्वीकार किया गया। कभी हर मोर्चे पर पीएम मोदी का विरोध करने वाले उमर अज्जुल्ला



अब उनके शासन के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार कर रहे हैं। नीतियों से लेकर सुधारों तकए पूर्व विरोधी मोदी मोदी करने लगे हैं। उमर अज्जुल्ला ने सार्वजनिक मंच से कहा कि आपने कहा कि आप दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी को खत्म करने पर काम कर रहे हैं और यह वास्तव में आपके काम से साबित होता है। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों से कहा था कि बहुत जल्द चुनाव होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। आपने अपनी बात रखी और 4 महीने के भीतर चुनाव हुए।

प्रियंका चतुर्वेदी से एक पॉडकास्ट में उनके फेवरेट लीडर के बारे में पूछा गया था। प्रियंका चतुर्वेदी ने बगैर किसी लाग

लपेट के सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे महान नेता तो बताया हीए कुछ देर तक उनकी तारीफमें कसीदे भी पढ़ती रहीं। न्होंने कहा कि पीएम मोदी लोगों से जुड़ने में माहिर हैंए खासकर युवाओं और महिलाओं से। प्रियंका चतुर्वेदी ने माना कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्होंने एक बड़े वोट बैंक को प्रभावित किया है। बीजेपी की प्रमुख आलोचक रही शरद पवार की बेटी और एनसीपी ;शरद पवारइ की नेता सुप्रिया सुले ने हाल ही में भारतीय रेलवे की तारीफ कर दी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में रेलवे द्वारा किए गए कार्य की सराहना की। जिस पर रेल मंत्री अश्विनी

हिन्दुस्तान में हिन्दू राज करेंगे ...तो बांग्लादेश बन जाएगा बंगाल-

कोलकाता ११/०१ (संवाददाता): राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता ;एलओपीड सुर्वेदु अधिकारी ने रामनवमी पर तृणमूल सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि भारत में हिंदू शासन करेंगे और 2026 के चुनावों में ममता बनर्जी सरकार जल्द ही सज़ा से बाहर हो जाएगी। विपक्ष के नेता ने इस बात पर भी जोर दिया कि 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस द्वारा अल्पसंख्यक वोट बैंक को खुश करने और एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है और राज्य के विभिन्न हिस्सों में पुलिस द्वारा रामनवमी को रोकने



का प्रयास तृणमूल कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है।अधिकारी ने दावा किया ष्हिन्दुस्तान में हिन्दू राज करेंगे और जो हिन्दुओं के लिए काम करेंगेए वे पश्चिम बंगाल में राज करेंगे। ममता बनर्जी अगर सज़ा में रहीं तो राज्य की स्थिति बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। उनके शासन के

दिन अब गिने.चुने रह गए हैं। हिंदू अब एक समुदाय के प्रति उनके खुलेआम तुष्टीकरण और रामनवमी उत्सव को कुचलने के प्रयासों को स्वीकार नहीं करेंगे। भाजपा नेता ने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू राज करेंगे और बंगाल में हिंदुओं के कल्याण के लिए काम करने

वाले सज़ा में रहेंगे। दिल्ली भाजपा ने जीत ली है और अब बंगाल की बारी है। ममता बनर्जी को मैंने हराया था। 2026 में भवानीपुर में भाजपा उज्जमीदवार से फिर हारेगी। उन्होंने दावा किया कि हर बार चुनाव से पहले ममता बनर्जी एक ख़ास समुदाय के वोट बैंक को मजबूत करने के लिए फुफ्फुा शरीफ जाती हैं। 2016 में वह दस महीने के भीतर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जो दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। दस महीने के भीतर विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने हिंदू सनातनियों और एससी.एसटी से एक साथ आकर भाजपा को वोट देने का



विविध समाचार



कब पड़ेगा माघ मेला का पहला शाही स्नान? तारीख और जरूरी जानकारीयां

महकुंभ के बाद अब प्रयागराज में नए साल की शुरुआत महा माघ मेले के साथ हो रही है। यह मेला 3 जनवरी 2026 को शुरू होगा। जहां पर बड़े स्तर पर संत और अन्य लोग पहुंचकर गंगा स्नान करेंगे। ऐसे में यहां पर स्नान और सुरक्षा से जुड़े सभी कार्य किए जा रहे हैं, ताकि लोग पहला शाही स्नान करने आए तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो। ऐसे में आर्टिकल में जानते हैं कि इस साल माघ मेले का शाही स्नान कब है। इसके बारे में पूर्ण जानकारी को आप यहां जानें।

माघ मेला कब शुरू हो रहा है?

माघ मेला 2026, 3 जनवरी से 15 फरवरी तक चलने वाला है। ऐसे में इस मेले में लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और गंगा में स्नान करेंगे। इसका पहला शाही स्नान 3 जनवरी को होगा। इस दिन पौष पूर्णिमा पड़ रही है। इस दिन स्नान का काफी महत्व होता है।

माघ मेले का पहला शाही स्नान कब है?

माघ मेले में पहला शाही स्नान 3 जनवरी को होगा। इस दिन पौष पूर्णिमा की तिथि पड़ रही है। इस दिन से ही इसी के साथ कल्पवास शुरू हो जाएगा। ऐसे में स्नान के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे। आप भी शाही स्नान के लिए 3 जनवरी को माघ मेला जो प्रयागराज में लग रहा है। यहां जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पौष पूर्णिमा के दिन पश्चिम दिशा में स्नान करते हैं तो इसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आप साल की पहली पूर्णिमा के दिन स्नान कर सकते हैं।

माघ मेले से जुड़ी जरूरी जानकारीयां

- माघ मेले में अगर आप भी स्नान करने जा रहे हैं, तो अपने साथ सभी चीजों का ध्यान जरूर रखें।
- अगर आप यहां पर किसी खास पूजा के लिए जा रहे हैं, तो सभी सामग्री का खास ध्यान रखें।
- माघ मेले में पूजा से पहले आप स्नान करें। इसके बाद ही पूजा करवाएं।
- अगर आप पौष पूर्णिमा में स्नान कर रही हैं, तो इस दिन आप कल्पवास की शुरुआत भी कर सकते हैं।
- माघ मेले में पूजा से जुड़ी सभी चीजों के लिए आप यहां पर लगी दुकानों से जाकर सामग्री ले सकते हैं।

सकट चौथ पूजा में शामिल करें ये खास चीजें, संतान की लंबी उम्र का मिलेगा आशीर्वाद

इस साल 6 जनवरी 2026 को सकट चौथ का पावन पर्व मनाया जा रहा है। यह व्रत हिंदू पंचांग की माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर रखा जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, यह दिन सकट माता और भगवान गणेश की उपासना को समर्पित है। इस दिन विशेष रूप से महिलाएं अपनी संतान के सुख, उनकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की कामना के लिए उपास रखती हैं। वहीं इस दिन की पूजा में तिल का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि, सकट चौथ पर तिल का पहाड़ बनाकर उसे सिक्कों की सहायता से बीच से काटना अत्यंत शुभ होता है। यह किया जीवन के दुखों, बाधाओं और नकारात्मकता के अंत का प्रतीक मानी गई है। इसके अलावा सकट चौथ की पूजा जीवन में कई तरह के बदलाव लेकर आती है। इसलिए गणेश पूजन हमेशा संपूर्ण सामग्रियों के साथ करनी चाहिए। यह शुभ होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं।

पूजन सामग्री

चीनी और अक्षत गुलाब, जनेऊ, सुपारी पान का पत्ता, हल्दी के साबुआ, मौली, तिल और फूल मालाएं शामिल कर ले

लौंग, गणपति की मूर्ति, लाल फूल 21 गांठ दुर्वा, सिंदूर इत्र, अवीर, इलायची, मेहंदी, दीप, घूप तिल के लड्डू, गंगाजल दूध, गाय का घी



लकड़ी की चौकी, मोदक मौसमी फल, व्रत कथा की पुस्तक पीला कपड़ा, कलश, रोली गाय का घी, तिल से बना भोग दान सामग्री, कुछ हरी चीजें दान के लिए, सकट माता की तस्वीर शुभ मुहूर्त और चंदोदय चांद निकलने का समय- रात 8 बजकर 54 मिनट

लाभ - उन्नति - सुबह 11:09 से 12:27 अमृत - सर्वोत्तम - दोपहर 12:27 से 01:45 शुभ - उत्तम - दोपहर 03:03 से 04:21 लाभ - उन्नति - शाम 07:21 से 09:03 1.वक्रतुण्ड महाकाय सूर्योदित समप्रभ।

निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥ 2 .गणपूज्यो वक्रतुण्ड एकदंष्ट्री त्रियम्बकः । नीलपीवो लम्बोदरो विकटो विघ्नराजकः ॥ धूम्रवर्णो भालवन्दो दशमस्तु विनायकः । गणपतिहस्तमुखो द्वादशारे यजेद्गणम् ॥ सकट चौथ व्रत कथा हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान गणेश अपने भक्तों की बाधाओं को दूर करने और किसी भी संकट (संकट/सकट) को हल करने के लिए जाने जाते हैं। इस त्यौहार का नाम भी सकट चौथ है। कथा के अनुसार एक दिन, माता पार्वती स्नान करने गईं और उन्होंने भगवान गणेश को बाहर पहना देने और किसी को भी अंदर न आने देने का आदेश दिया। अपनी माता के निर्देश का पालन करते हुए, उन्होंने भगवान शिव को भी अंदर नहीं आने दिया, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती ने अपने पुत्र की यह अवस्था देखी, तो वे रोने लगीं और अपने पति से गणेश को पुनर्जीवित करने की विनती की। अनेक प्रयासों के बाद, एक हाथी का सिर काटकर गणेश को दूसरा जीवन दिया गया। उसी दिन, उन्हें किसी भी उत्सव या आरंभ के दौरान सर्वप्रथम पूजा जाने का स्थान प्राप्त हुआ। सकट चौथ पर, उन्हें सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसलिए यह दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए शुभ माना जाता है।

गलती से भी घर में न लगाएं मां लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर, आ सकती है आर्थिक तंगी



सनातन धर्म में मां लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मां लक्ष्मी जिस भी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाती हैं उसपर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करता है उसे कभी धन-दौलत की कमी नहीं होती है। इसलिए लोग मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अक्सर लोग अपने घरों में मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर लगाते हैं। घर में मां लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति लगाना शुभ माना जाता है। अगर कोई बार लोग जाने-अनजाने में मां लक्ष्मी को कुछ ऐसी तस्वीर लग लेते हैं जो भूलकर भी घर में नहीं लगनी चाहिए। असल में उन तस्वीरों को लगाने से घर में कगाली आ सकती है। ऐसे में माता लक्ष्मी की तस्वीर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए, ऐसी तस्वीर घर में रखने से मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित होने का खतरा रहता है।

न लगाएं उल्टी के साथ मां लक्ष्मी की तस्वीर

मां लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। हालांकि, उल्टी को उनका वाहन माना जाता है, फिर भी मां लक्ष्मी की उल्टी पर सवार तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जब मां लक्ष्मी के पास उल्टी की मूर्ति होती है तो वो उल्टी पर सवार होकर चली जाती हैं। इसलिए, ऐसी तस्वीर घर में रखने से मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित होने का खतरा रहता है।

न लगाएं ऐसी तस्वीर शस्त्रों के अनुसार, मां लक्ष्मी की खड़ी हुई मुद्रा वाली तस्वीर घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि खड़ी हुई मुद्रा में मां लक्ष्मी का विजय उनकी चंचलता को दर्शाती है। जब मां लक्ष्मी खड़ी होती हैं, तो यह इस बात का संकेत होता है कि वे एक अलग विचार नहीं रखेंगी और जल्द ही घर से चली जाएंगी। इसलिए, मां लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर घर में रखने से धन और समृद्धि में कमी आ सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां लक्ष्मी की बैठी हुई मुद्रा वाली तस्वीर को ही घर में स्थापित करना शुभ माना जाता है। ऐसी तस्वीर होती है शुभ

मां लक्ष्मी की कमल के फूल पर विराजमान और सोने के सिक्कों बरसते हुए तस्वीर को शुभ माना जाता है। यह विजय देवी लक्ष्मी की धन और समृद्धि प्रदान करने वाली शक्ति का प्रतीक है। ऐसी तस्वीर घर में रखने से धन-धान्य की वृद्धि होती है।

अश्लीलता की मुद्रा

घर में मां लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगाना शुभ होता है, जिसमें वे अश्लीलता मुद्रा में बैठी हों। ऐसी तस्वीर से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता लक्ष्मी हमेशा कृपा बरसाती हैं। यह तस्वीर धन और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है।

पर्स में नहीं टिक रहा पैसा, आमदनी से ज्यादा खर्च से हैं परेशान, अपनाएं ये आसान वास्तु टिप्स

अक्सर लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि मेहनत करने के बाद भी उनके पास पैसा नहीं टिक पाता। अच्छी खासी कमाई होने के बाद भी खर्च इतने बढ़ जाते हैं कि बचत करना नामुमकिन हो जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इसका कारण घर या ऑफिस में कुछ छोट-छोटे वास्तु दोष होते हैं, जो धन के प्रवाह को रोकते हैं। समय रहते इन दोषों को दूर करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। आइए जानते हैं वास्तु के कुछ आसान टिप्स जो इन दोषों को दूर कर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं।

कुबेर देवता का मंगाने के उपाय

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की उत्तर दिशा धन और समृद्धि से जुड़ी होती है, जिसके रखनी धन के देवता कुबेर हैं। इन क्षेत्र को साफ-सुथरा रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। उत्तर दिशा में पानी का फव्वारा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पानी के फव्वारे से बहता पानी धन के प्रवाह से जुड़ा होता है।

रसोई घर के लिए शुभ दिशा

रसोई घर को सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक माना जाता है। यह घर के स्वास्थ्य और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वास्तु के अनुसार, रसोई घर के दक्षिण-पूर्व दिशा में होना चाहिए। ध्यान रखें कि घर की उत्तर दिशा में रसोई घर न बनाएं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

जीवन में आने वाली बाधाएं कैसे होंगी दूर, जानें इन उपायों को

जीवन में कई बार अनेक प्रकार की बाधाएं आसक्त हो जाती हैं जिससे व्यक्ति हताश, निराश और दुखी हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए नौकरी, व्यवसाय या व्यापार आदि करता है। कभी-कभी कार्यक्षेत्र में एवं घर-परिवार के कार्यों में भी बाधाएं उठ खड़ी होती हैं, जिनका प्रायः कोई समाधान नहीं दिखाई देता। ज्योतिष में इन कार्य बाधाओं का नाश करने के अनेक उपाय दिये गये हैं।

तुलसी के तीन-चार पत्तों की गड़गा करके घर से बाहर जाने पर सभी प्रकार की कार्य बाधा दूर हो जाती है।

प्रातःकाल दीप जलाकर उसमें दो फूल वाली जलजित लौंग डाल दें, उसके बाद घर से बाहर निकले, आगे के कार्यों में अपने वाली समस्त बाधाएं समाप्त हो जायेंगी।

घर से बाहर निकलते समय एक निश्चित धनराशि जिसमें एक सिक्का जरूर हो, हाथ में ले लें। उसे किसी मिश्रण को देने से उसके अश्लीलता से वह कार्य बाधा रहित होगा, जिसके लिए आप जा रहे हैं।

नित्य प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर आश्विन इन्द्र स्नान एवं राम रत्न स्नान का पाठ करने से कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं तथा स्वयं की रक्षा होती है।



लंगरे से व्याघर-व्याख्या की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं।

वाघन और हल्दी को पीसकर उसके द्वारा घर के प्रवेश द्वार पर ऊँ और स्वस्तिक बना दें, आपका घर सभी प्रकार की बाधाओं से सुरक्षित रहेगा।

नित्य प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर आश्विन इन्द्र स्नान एवं राम रत्न स्नान का पाठ करने से कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं तथा स्वयं की रक्षा होती है।

नौकरी, साक्षात्कार या किसी विशेष कार्य हेतु घर से बाहर निकलते समय गुड़, साबुन, मिठई या दही खा लें, आपके कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी।

शनिवार के दिन सरसों का तेल या काली उड़द का दान करने से कार्यों की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं।

इन छोट-छोटे उपायों की सहायता से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी ज्योतिषी को अपना सही-सही जन्म समय

बताकर जन्म कुण्डली के माध्यम से अपने उपर चलने वाली नकारात्मक, अकारण दशा एवं ग्रह गोलों को समझकर व्यक्तिगत उपाय करने से सटीकता के साथ विघ्न-बाधा दूर होती है।

जन्मधर्म में प्रबल भाव के स्वामी लग्नेश, पवन भाव के स्वामी धनमेस एवं नभ भाव के स्वामी भार्गव इत्यादि का रत्न किसी ज्ञानी ज्योतिषी से पूछकर सही स्थिति से प्राण प्रीति के बाद धारण करने से जीवन में मनोवांछित परिणाम प्राप्त होते हैं तथा विघ्न-बाधाएं न्यूनतम हो जाती हैं।



पौष माह में भगवान विष्णु को पीला नहीं, लाल चंदन ही क्यों लगाते हैं?

पौष माह भगवान विष्णु को समर्पित है। पौष माह में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि पौष माह में श्री हरि नारायण की आराधना करने से व्यक्ति के दुख दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु का सांनिध्य प्राप्त होता है। वहीं, शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि पौष माह के दौरान भगवान विष्णु का श्रृंगार करना भी शुभ होता है। हालांकि, यह भी उल्लेखित है कि पौष माह में भगवान विष्णु को पीला नहीं बल्कि लाल चंदन लगाना चाहिए। ऐसे में ज्योतिषाचार्य राधाचंद्रांत वत्स से आइये जानते हैं कि क्यों पौष माह में लगाया जाता है श्री हरि विष्णु को लाल चंदन।

पौष माह में भगवान विष्णु को लाल चंदन लगाने के लाभ

- पौष माह के दौरान भगवान विष्णु को लाल चंदन लगाने से सूर्य की कुडली में स्थिति मजबूत होती है। सूर्य यह के मजबूत होने से भाग्य का साथ मिलने लगता है।
- सौभाग्य में वृद्धि होती है और सफलता प्राप्ति में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं।
- तरकी के मार्ग खुलने लगते हैं।
- पौष माह में भगवान विष्णु को लाल चंदन लगाने से मंगल ग्रह की शुभता भी मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लाल रंग मंगल का प्रतीक माना जाता है। मंगल ग्रह के शुभ प्रभाव से सांत्विक कार्य, विशेष रूप से विवाह में आ रही बाधाएं या फिर

- वैवाहिक जीवन के दुख दूर होते हैं।
- पौष माह में भगवान विष्णु को लाल चंदन लगाना इसलिए भी शुभ माना जाता है क्योंकि इससे उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता होती है। असल में लाल रंग मां लक्ष्मी का प्रिय है। मां लक्ष्मी का वास जहां होता है वहीं श्री हरि विराजते हैं। लाल चंदन विष्णु जी को लगाने से मां लक्ष्मी का वास बना रहता है।
- पौष माह में लाल चंदन भगवान विष्णु को लगाने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं और उनका क्रोध शांत हो जाता है। भगवान विष्णु को पित्रो का देवता माना गया है। ऐसे में पौष माह के दौरान लाल चंदन भगवान विष्णु को लगाने से पितृ दोष से भी राहत मिलती है और शुभ कार्य सफल होते हैं।

कलिंग समाचार



संपादकीय

सोमवार 12 जनवरी 2026

एंजेल चकमा की मौत, देश के लिए सबक

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा से आए छात्र एंजेल चकमा की नस्लवादी नफरत में हत्या कर दी गई। इस घटना पर अब उत्तराखंड से लेकर त्रिपुरा तक विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। पूर्वोत्तर के छात्र अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वहीं अब भाजपा के नेता भी इस घटना को दुखद और चिंतनीय बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में नस्लवाद और भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। किसी भी जाति, नस्ल या धर्म के लोगों का मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल पूर्वोत्तर के लोग ही नहीं, बल्कि सभी को इस तरह की घटनाओं से दुखी होना चाहिए, क्योंकि यह किसी के साथ भी हो सकता है। एक बेकसूर नागरिक को केवल उसके चेहरे-मोहरे के कारण मार देना दुख और नाराजगी की बात तो है ही, उससे भी अधिक गहरी चिंता की बात है कि एक समाज के तौर पर हम पागलपन के किस दौर में पहुंचा दिए गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को कपड़ों से पहचान करने के लिए उकसाया तो अब उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए लोग कपड़ों के साथ-साथ खान-पान, नाम, नैन-नक्श से भी पहचान करने लगे हैं कि कौन हमारे जैसा है और कौन नहीं। जो हमारी तरह नहीं है, बहुसं यकों में शामिल नहीं है, उसे अल्पसं यक भी न रहने दिया जाए, बल्कि उसका अस्तित्व ही मिटा दिया जाए, इसी उन्मादी सोच का शिकार देश हो चुका है। भाजपा ने सत्ता पाने और उस पर जमे रहने के लिए लोगों में जो फूट डालनी शुरू की है, अब उसकी पराकाष्ठा देखी जा सकती है। किरण रिजीजू को अब अगर लग रहा है कि जाति, नस्ल या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो ऐसा ही विरोध उन्हें उस वक्त भी करना था जब सैंटा क्लॉज की टोपी पहनने या बेचने वालों को प्रताड़ित किया गया। जब जन्मदिन के जश्न में बजरंग दल के गुंडे केवल इसलिए घुसकर मारपीट करने लगे, क्योंकि उसमें अल्पसं यक लोग भी थे। अगर अखलाक की लिंगिंग के बाद ही किरण रिजीजू भीड़ की हिंसा के खिलाफ बोलते या झारखंड में माॅब लिंगिंग के आरोपियों को जब भाजपा नेता जयंत सिन्हा माला पहना रहे थे, तब उनकी मुखालफत करते, तब तो उनकी चिंता जायज लगती। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि पूर्वोत्तर में भाजपा की स्थिति कमजोर न हो जाए, इस डर से किरण रिजीजू पीड़ित के पक्ष में बोल रहे हैं। गनीमत यही है कि वो बोल रहे हैं, वर्ना देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को तो शायद ऐसी घटनाएं संबोधित करने लायक लगती ही नहीं हैं। वैसे भी इस समय उनका पूरा ध्यान इस समय बंगाल चुनाव पर हैं, जहां से घुसपैठियों को चुन-चुन कर निकालने की प्रतिबद्धता मोदी-शाह दिखा रहे हैं। हालांकि वे अब तक ये नहीं बता पाए हैं कि इससे पहले झारखंड, दिल्ली और बिहार में उन्हें कितने घुसपैठिए मिले हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है। घुसपैठिए का डर बढ़ाकर भी देश में अल्पसं यकों और बांग्लाभाषियों के लिए खतरे बढ़ा दिए गए हैं। मजदूरी या अन्य कार्यों में रत बांग्लाभाषियों को कई बार घुसपैठिए होने के नाम पर प्रताड़ित होना पड़ा है। इस सिलसिले में कांग्रेस नेता अधोर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चिंता जाहिर की है कि प्रवासी बंगाली मजदूरों के साथ हो रहे भेदभाव पर कार्रवाई की जाए। वैसे उत्तराखंड के मु यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 29 तारीख को पीड़ित के पिता से फोन पर बात की और आश्वासन दिया कि कोई ब श नही जाएगा। उन्होंने त्रिपुरा की भाजपा सरकार के मु यमंत्री माणिक साहा से भी फोन पर बात की। पीड़ित के पिता से बात करते हुए मु यमंत्री धामी ने बाकायदा वीडियो बनवाया और उसे सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। सवाल ये है कि क्या भाजपा के लोगों में शर्म और संवेदनशीलता का भाव रंचमात्र भी बचा है या नहीं। क्योंकि 9 तारीख की घटना पर प्रतिक्रिया देने में मु यमंत्री को पूरे 20 दिन लग गए। जबकि घटना उसी देहरादून में हुई, जहां वो रहते हैं।

सिर्फ नारा नहीं था नरेगा के तहत काम का अधिकार

डॉ. अजीत रानाडे
संसदीय स्थायी समिति के संदर्भ के बिना और राज्यों, श्रमिक संगठनों या नागरिक समाज के साथ गंभीर परामर्श किए बिना वीबी-जी राम जी विधेयक को जिस तरह से पेश तथा पारित किया गया है, वह भी उतना ही आपत्तिजनक है। एक ऐसा कानून, जो नागरिक और राज्य के बीच संतुलन को मौलिक रूप से बदल देता है,उसके लिए यह प्रक्रियागत जल्दबाजी लोकतांत्रिक मानदंडों में फिट नहीं बैठती है।

विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) 2025 (वीबी-जी राम जी विधेयक)% का पारित होना भारत के सबसे परिणामदायी सामाजिक कानूनों में से एक के निर्णायक विराम का प्रतीक है। इसने 2005 के ऐतिहासिक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) का स्थान लिया जिसे बाद में महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया था। सरकार इस बात पर जोर देती है कि नया कानून एक ऐसा सुधार है जो गारंटीकृत कार्य की सीमा को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर देता है लेकिन यह दावा सरसरी तौर से भी खरा नहीं उतरता है। नया विधेयक वास्तव में कहीं अधिक परेशान करने वाला है- यह काम करने के न्यायोचित अधिकार को समाप्त करता है, नियंत्रण को पुनर्केन्द्रीकृत करता है, राजकोषीय बोझ को राज्यों को स्थानांतरित करता है और ग्रामीण भारत में श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति को कमजोर करता है।

नरेगा कभी भी सिर्फ एक कल्याणकारी योजना नहीं थी। यह संविधान के अनुच्छेद 41-काम करने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए राज्य के दायित्व- को लागू करने योग्य पात्रता में बदलने वाला एक कानूनी नवाचार था। यदि मांग के 15 दिनों के भीतर काम



नहीं दिया जाता था तो राज्य कानूनी रूप से बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने के लिए बाध्य था। नरेगा के तहत रोजगार-मांग-आधारित, सार्वभौमिक था और यह अधिकार न्यायोचित था। वीबी-जी राम जी विधेयक इस अधिकार-आधारित, मांग आधारित ढांचे को आपूर्ति-संचालित, बजट-कैण्ड योजना के साथ प्रतिस्थापित करता है जो शर्तों है तथा जिसकी गारंटी केंद्रीय आवंटन और प्रशासनिक विवेक पर है।

याद रखने वाली बात यह है कि नरेगा की जड़ें महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना (ईजीएस) में थीं। 1970 के दशक की शुरुआत में पड़े विशाकारी सूखे का मुकाबला करने के लिए बनाए गये ईजीएस को शहरी श्रमिकों को समर्पित कर वित्तपोषित और ग्रामीण रोजगार की वैधानिक गारंटी द्वारा समर्थित किया गया था। इसकी विशेषता इसकी सरलता में निहित है- मांग पर काम, स्थानीय रूप से निर्धारित सार्वजनिक कार्य और मजदूरी का भुगतान श्रमिक के अधिकार के रूप में होना। यह नरेगा के लिए बौद्धिक और संस्थागत टे प्लेट बन गया। ईजीएस का डिजाइन गांधीवादी नेता वीएस पागे के नेतृत्व में लागू की गई पायलट परियोजनाओं से प्रेरित था।

ईजीएस ने एक राजनीतिक सच्चाई का भी खुलासा किया जो आज भी प्रासंगिक है। इसने

मजदूरी के लिए एक धरातल निर्धारित करके तथा श्रमिकों को बाहर निकलने का विकल्प देकर श्रमिकों की जमींदारों और ठेकेदारों पर निर्भरता को कम कर दिया। आश्चर्य की बात नहीं है कि इसे ज़मींदार अभिजात वर्ग के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा जिन्होंने %श्रम की कमी% और बढ़ती मजदूरी के बारे में शिकायत की। नए विधेयक का प्रावधान कृषि मौसमों के चरम के दौरान रोजगार में 60 दिनों के ठहराव को अनुमति देता है जो जाहिरा तौर पर %श्रम उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने% के लिए तटस्थ नीति डिजाइन की तरह कम और उन लोगों की सुविधा के लिए रियायत की तरह अधिक है जो लंबे समय से नरेगा के ग्रामीण श्रम बाजारों पर प्रभाव से नाराज हैं।

सरकार के बचाव का केंद्र बिंदु गारंटीकृत रोजगार को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना है लेकिन यह काफी हद तक प्रतीकात्मक है। यहां तक कि नरेगा के तहत भी अधिकांश वर्षों में वास्तव में परिवारों के एक छोटे से हिस्से को ही पूरे 100 दिनों का काम मिलता था।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नया विधेयक केंद्र द्वारा निर्धारित %राज्यवार मानक आवंटन% के माध्यम से कुल व्यय को सीमित करता है। इस सीमा से अधिक का कोई भी खर्च केंद्र द्वारा निर्धारित

प्रक्रियाओं का पालन करते हुए राज्यों द्वारा वहन किया जाना चाहिए। कानून में बजट कैप को शामिल कर यह विधेयक एक कानूनी गारंटी को केंद्रीय राशन कार्यक्रम में परिवर्तित करता है।

अपनी तमाम कमियों के बावजूद नरेगा ने सहकारी संघवाद के व्यावहारिक रूप को मूर्त रूप दिया था। केंद्र ने यह मानते हुए कि उच्च बेरोजगारी वाले गरीब राज्यों में भी कमजोर राजकोषीय क्षमता है, पूरी मजदूरी लागत तथा अधिकांश सामग्री लागत को वहन किया। वीबी-जी राम जी विधेयक इस तर्क को पलट देता है। प्रस्तावित 60%40 लागत-साझे का पैटर्न राज्यों पर अनुमानात् सालाना 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का बड़ा अतिरिक्त बोझ डालता है, खासतौर पर ऐसे समय में जब जीएसटी और उधार लेने की बाधाओं के कारण राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता पहले ही खत्म हो चुकी है।

यह केवल एक राजकोषीय मुद्दा नहीं है बल्कि यह एक संवैधानिक मुद्दा भी है। रोजगार और लोक निर्माण पूरी तरह से राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं तथा 11वीं अनुसूची के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नया विधेयक इस बात का उदाहरण है कि विशेषज्ञों ने इसे केंद्र की %सातवीं अनुसूची में चोरी छिपे घुसना% कहा है- संवैधानिक रूप से राज्यों को सौंपे गए

विषयों पर केंद्रीय नियंत्रण का विस्तार करना जबकि राज्यों को कार्यान्वयन की वित्तीय और राजनीतिक लागतों को वहन करने के लिए छोड़ देता है। विधेयक के समर्थकों का तर्क है कि नरेगा अक्षम, भ्रष्टाचार प्रवण और प्रशासनिक रूप से कठोर था लेकिन ये कार्यान्वयन की समस्याएं थीं, डिजाइन की नहीं।

विलंबित भुगतान, बायोमेट्रिक विफलताओं और बहिष्करण त्रुटियों का समाधान संस्थागत सुधार के माध्यम से होना चाहिए था, न कि कानूनी ताकत कम पड़ने के कारण ऐसा किया जाना था। इसके अलावा परियोजना व कार्यों के चयन के लिए केंद्रीकृत एआई-आधारित डैशबोर्ड शुरू करके नरेगा की स्थानीय सरकार और समुदाय की महत्वपूर्ण स्वायत्तता जैसी विशेषता को छीन लिया गया है।

नरेगा की सबसे मौलिक विशेषता इसकी सार्वभौमिकता थी। यह गरीबी रेखाओं, लाभार्थी सूचियों या लक्ष्यीकरण त्रुटियों पर निर्भर नहीं था। शारीरिक कार्य करने का इच्छुक कोई भी अकुशल व्यक्ति रोजगार की मांग कर सकता है। इस स्व-लक्ष्यीकरण डिजाइन ने बहिष्करण एवं रिसाव को कम किया। वीबी-जी राम जी विधेयक इस सिद्धांत से हटकर केंद्र को विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्रों को अधिसूचित करने की अनुमति देता है जहां रोजगार प्रदान किया जाएगा। एक गारंटी जो केवल वहीं लागू होती है जहां केंद्र इसे लागू करने का विकल्प चुनता है। यह शर्तों में एक विरोधाभास है।

कोविड-19 के भीषण संकट के दौरान नरेगा ने एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम किया, ग्रामीण मांग को बनाए रखा और बड़े पैमाने पर अभावग्रस्तता को रोका। इसने महिलाओं की श्रम भागीदारी

को भी बढ़ाया है, सबसे गरीब श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति में सुधार किया है तथा पलायन को कम किया है। ये दुष्प्रभाव नहीं थे बल्कि वे इसके डिजाइन के केंद्र में थे। दुनिया के सबसे असमान श्रम बाजारों में से एक में श्रम की सौदेबाजी की शक्ति में मामूली सुधार करने वाले कार्यक्रम को सफलता का जश्न मनाया जाना चाहिए। न कि उसे नष्ट किया जाना चाहिए।

संसदीय स्थायी समिति के संदर्भ के बिना और राज्यों, श्रमिक संगठनों या नागरिक समाज के साथ गंभीर परामर्श किए बिना वीबी-जी राम जी विधेयक को जिस तरह से पेश तथा पारित किया गया है, वह भी उतना ही आपत्तिजनक है। एक ऐसा कानून, जो नागरिक और राज्य के बीच संतुलन को मौलिक रूप से बदल देता है,उसके लिए यह प्रक्रियागत जल्दबाजी लोकतांत्रिक मानदंडों में फिट नहीं बैठती है।

अधिकार-आधारित ढांचे का मतलब है कि राज्य अपने नागरिकों को स मान के साथ काम करना चाहता है न कि उन्हें दान देने जैसा एहसान दिलाने की कोशिश करता है। महाराष्ट्र के ईजीएस ने आधी सदी पहले यह स मान दिलाया था। नरेगा ने उस नैतिक अंतर्दृष्टि का राष्ट्रीयकरण किया। नया विधेयक इससे पीछे हट जाता है।

2047 तक %विकसित भारत% बनने की आकांक्षा रखने वाले राष्ट्र को सामाजिक नागरिकता और सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करना चाहिए, न कि इसे कम करना चाहिए। नरेगा में सुधार आवश्यक तथा वांछनीय दोनों था। एक विवेकाधीन योजना के साथ एक न्यायसंगत अधिकार को बदलना न तो सुधार है और न ही प्रगति। यह एक संवैधानिक, आर्थिक व नैतिक आधार पर पीछे हटने वाला कदम है।

तेल आपूर्ति के गणित को बदल रही है भूराजनीति

के रवींद्रन

अमेरिका रिकॉर्ड स्तर के करीब पंप करना जारी रखे हुए है, ब्राजील और गुयाना और बैरल जोड़ रहे हैं, और कई ओईसीडी देशों में मांग फिर से बन रही है।

इस पृष्ठभूमि में, रूसी बैरल के एक ज़्यादा सामान्य व्यापार प्रणाली में संभावित जुड़ाव का बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा है। फरवरी 2021 के बाद पहली बार तेल की कीमतों 60 प्रति बैरल से नीचे आ गई हैं और यूरोपियन गैस की कीमतों में भारी गिरावट अन्य वस्तुओं में चक्रीय गिरावट से कहीं ज़्यादा है। ये ऐसे समय में भूराजनीतिक जोखिम की तेज़ी से पुनर्मूल्य निर्धारण का संकेत देते हैं जब कूटनीति, ऊर्ध्वगामी होने के बजाय, बाजार की मानसिकता पर हावी होने लगी है। नवंबर के बीच से यूरोपियन गैस की कीमतों में लगभग 16 प्रतिशत की गिरावट और कच्चे तेल में नई कमजोरी के बाद ऐसे संकेत मिले हैं कि अगर यूक्रेन विवाद खत्म करने के लिए बातचीत आगे बढ़ती है तो रूसी तेल कंपनियों पर लगे प्रतिबंध में ढील दी जा सकती है। यह संभावना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे से और मजबूत हुई है कि युद्ध के किसी भी पहले के चरण

की तुलना में समझौता ज़्यादा करीब हो सकता है।

बाजार ने ठोस नीतिगत बदलावों पर कम और बदलती उ मीदों पर ज़्यादा प्रतिक्रिया दी है। 2022 की शुरुआत से, तेल और गैस की कीमतों में काफी भूराजनीतिक वृद्धि रही है, जो आपूर्ति में रुकावट, प्रतिबंध और वैश्वक ऊर्जा व्यापार के टूटने के डर से जुड़ा है। वह वृद्धि अब खत्म हो रही है। अमेरिका रिकॉर्ड स्तर के करीब पंप करना जारी रखे हुए है, ब्राजील और गुयाना और बैरल जोड़ रहे हैं, और कई ओईसीडी देशों में मांग फिर से बन रही है। इस पृष्ठभूमि में, रूसी बैरल के एक ज़्यादा सामान्य व्यापार प्रणाली में संभावित जुड़ाव का बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा है।

कम तेल कीमतों और कच्चे तेल की अतिरिक्त आपूर्ति का साल होगा रूसी कच्चा तेल बाजार से कभी पूरी तरह गायब नहीं हुआ, लेकिन पारबंदियों की वजह से इसे छूट पर बेचने, लंबे शिपिंग रूट और खरीदारों का रूपा कम करने पर मजबूर होना पड़ा। अगर रूसी तेल कंपनियों पर लगी पारबंदियां हटा दी जाती हैं या उनमें ढील दी जाती है, तो माँस्को को उत्पादन और निर्यात में ज़्यादा लोच मिलेगी, जबकि खरीदारों

को कम अनुपालन जोखिम का सामना करना पड़ेगा। बड़े मार्केट के लिए, इसका मतलब होगा कि उपलब्ध आपूर्ति में असरदार बढ़ोतरी होगी और उन कमियों में कमी आएगी, जिन्होंने पिछले तीन सालों में बैलेंस को कड़ा किया है। ज़्यादा जाने बजट विश्लेषण रिपोर्ट महिला और बाल कल्याण उत्पाद युवा विकास कार्यक्रम स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं समाचार पत्र संपादकीय लेख उत्तर प्रदेश समाचार राजनीतिक विश्लेषण सेवा सड़क सुरक्षा उत्पाद पेपर,छद्मश्र ऋद्धुल -ललित सुरजन की कलम से - गोवा में चार दिन यूरोपियन गैस की कीमतों भी कुछ ऐसी ही कहानी कहती हैं।

हालांकि रूसी पाइपलाइन गैस के जल्द ही युद्ध से पहले के परिमाप पर लौटने की उ मीद नहीं है, लेकिन कोई भी कूटनीतिक नरमी उन जोखिमों को कम करती है जो 2022 से बाजार को परेशान कर रहे हैं। यूरोप ने एलएनजी आयात क्षमता,भंडारीकरणऔर मांग में कमी लाने में भारी निवेश किया है, जिससे यह ढांचा के हिसाब से ज़्यादा मजबूत बन गया है। फिर भी, कीमतों में माँस्को के साथ लंबे समय तक टकराव के डर से जुड़ा जोखिम प्रीमियम बना हुआ है। जैसे-जैसे

बातचीत की बातों पर भरोसा बढ़ रहा है, वह प्रीमियम कम हो गया है, जिससे सर्दी आने के बावजूद बेंचमार्क गैस की कीमतों में भारी गिरावट आई है।

कम तेल और गैस की कीमतें महंगाई के दबाव को कम करती हैं, व्यापार संतुलन में सुधार करती हैं, और केन्द्रीय बैंकों को ज़्यादा नीतिगत लोच देती हैं। खासकर यूरोप को गैस की कीमतों में लगातार राहत से फ़ायदा होगा, जो 2022 से औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता पर एक बड़ा बोझ रही हैं। रसायन, धातु, और रासायनिक खाद जैसे ऊर्जा की गहनता वाले क्षेत्र में लाभ में सुधार हो सकता है, जबकि घरों को गर्म रखने में और बिजली का खर्च कम होगा।

फिर भी, लंबे समय की अनिश्चितताएं भी हैं। कीमतों में लंबे समय तक कमी से अपस्ट्रीम तेल और गैस परियोजनाओं में निवेश कम हो सकता है, खासकर ज़्यादा लागत वाले क्षेत्रों में। यह जोखिम तब और भी ज़्यादा हो जाता है जब उत्पादक एक नई बाजार-शेयर की लड़ाई की उ मीद करते हैं जो कीमत की स्थिरता के बजाय मात्रा को प्राथमिकता देती है। आज कम निवेश से दशक के आखिर में

बाज़ार तंग हो सकते हैं, खासकर अगर मांग मौजूदा उ मीदों से ज़्यादा मजबूत साबित होती है। ज़्यादा जाने उत्तर प्रदेश समाचार मनोरंजन समाचार युवा विकास कार्यक्रम क्षेत्रीय समाचार ऐप दिल्ली समाचार हिंदी समाचार हिंदी भाषा के कोर्स समाचार पत्र सदस्यता राजनीतिक विश्लेषण सेवा बजट विश्लेषण रिपोर्ट ऊर्जा संक्रमण एक और मुश्किल पैदा करता है। खनिज ईंधन की कीमतों में कमी गैर पारंपरिक ऊर्जा उपायों को अपनाने की गति को धीमा कर सकती हैं। साथ ही, कम ऊर्जा लागत का सामना करने वाली सरकारों को जलवायु नीतियों को बनाए रखना या उन्हें और मजबूत करना राजनीतिक रूप से आसान लग सकता है। कुल असर हर क्षेत्र में अलग-अलग होगा, लेकिन भूराजनीतिक

कीमतों और संक्रमण के बीच तालमेल ऊर्जा बाजार की एक खास पहचान बने रहने की संभावना है। मौजूदा घटना के बारे में जो बात चौंकाने वाली है, वह है तेज़ी से माहौल का बदलना। पिछले तीन सालों में ज़्यादातर समय, ऊर्जा बाजार पर सबसे खराब हालात हावी थे जैसे यूक्रेन में तनाव बढ़ना, कड़े प्रतिबंध, और बड़े उत्पादकों द्वारा जानबूझकर आपूर्ति में कटौती। मौजूदा बिकवाली से पता चलता है कि व्यापारी अब तनाव कम होने, व्यापार के बहाव के सामान्य होने, और ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक आपूर्ति माहौल को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। यह आशावाद आखिरकार सही साबित होगा या नहीं, यह समझौता वार्ता के नतीजों और किसी भी राजनीतिक समझौते की स्थिरता पर निर्भर करेगा।





'बच्चों को बिगाड़ते घटिया बेव सीरिज और यू ट्यूब चैनल्स'

चंडीगढ़ ११/०१ (संवाददाता): वर्तमान समय में माता पिता के दिए गए संस्कार फीके पड़ते जा रहे हैं । कारण— बॉलीवुड की फिल्में, घर बिगाड़ने वाले टीवी सीरियल, वेब सीरीज, यूट्यूब — जिसमें एक बहुत बड़ा गिरोह शामिल हो गया है जो हमारे सनातनी बच्चों को बिगाड़ने में लगा हुआ हैस इनमें अनेक पाखंडी संत भी शामिल हैं। नादान बच्चे इनकी बातों को सही मान बैठते हैं। ये पाखंडी लोग उदहारण देकर समझायेंगे कि जब राम ने सीता को त्याग दिया तो तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं त्याग सकते हो अर्थात तलाक ले सकते

हो। अब इन मूर्खों को कौन समझाये कि माता सीता तो गंगाजल की तरह पवित्र थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक धोबी के कड़वे बोल सुनकर माता सीता के त्याग का फैसला कर लिया क्योंकि उन्होंने धोबी के विचारों को जनता का निर्णय माना और वो जनता के निर्णय के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे जिससे कोई यह नहीं कह सके कि सीता तो राजघराने की बहू है इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे जैसे साधारण लोगों पर ही अंगुलियां उठाई जाती हैं। भगवान राम ने यह साबित कर दिया था कि हमारे राज्य में सब एक समान है । यहां

पर राजा और प्रजा के लिये कोई अलग— अलग नियम नहीं हैं। 'रामायण हमें जीना सिखाती है' परिवार में किस तरह से रहना चाहिए यह बातें हमें रामायण सिखाती है। रामायण में सभी रिश्तों की मर्यादायें तय की गई हैंस रामायण हमें ही नहीं पूरे विश्व को जीना सिखाती है। 'बच्चों के पतन का कारण घटिया सिलेबस' जब तक पूरे देश में एक देश एक शिक्षा नीति एवं एक ही पाठ्यक्रम लागू नहीं होगा तब तक बच्चों को सही एवं चरित्र निर्माण करने वाली शिक्षा नहीं मिलेगी। सनातन विरोधी राज्य सरकारें अपने हिसाब से सिलेबस तय करती है। अकबर को महान

बताया जाता है, सम्राट अशोक को नहीं । महाराणा प्रताप ,छत्रपति शिवाजी महाराज,छत्रपति सम्भा जी ,झाँसी की रानी, अहिल्या बाई, संत तुलसी दास, संत तुकाराम जैसे, अनगिनत महापुरुषों को पाठ्यक्रम में समुचित स्थान नहीं दिया गया। इनकी गौरवमयी जीवनी को पढ़े बिना बच्चों में चरित्र निर्माण कहां से होगा। यही नहीं पाठ्यक्रम में रामायण एवं श्रीमद्भागवत कथा के प्रसंगों को भी अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का चोला पहन कर कब तक हमारी गौरवशाली भारतीय संस्कृति को नष्ट—भ्रष्ट किया जाता रहेगा? अब समय आ

गया है कि इस तरह का सिलेबस तैयार किया जाए जिससे बच्चों का चरित्र निर्माण हो। बच्चों के हाथ में स्मार्ट फोन हो या न हो लेकिन चरित्र निर्माण करने वाली पुस्तकें अवश्य होनी चाहिए। गीता प्रेस एवं अखिल भारतीय गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा द्वारा लिखित पुस्तकें एवं पत्रिकाएं बच्चों के लिए अमृत के समान हैं। इनको सही ज्ञान मिलेगा तो वे बॉलीवुड की बेसिरपैर की फिल्में, घर बिगाड़ने वाले टीवी सीरियल, अश्लील वेब सीरीज एवं यूट्यूब पर घटिया कंटेंट परोसने वाले पाखण्डी लोगों के चंगुल से बच सकेंगे।

जालंधर : स्कूल बस की चपेट में आकर 4 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत, परिजनों ने लगाया जाम

जालंधर ११/०१ (संवाददाता): आदमपुर से अलावलपुर की ओर जाने वाले हाईवे पर स्थित एस.डी. पब्लिक स्कूल में आज सुबह एक दर्दनाक चपेट में आकर यूकेजी में पढ़ने वाली 4 वर्षीय बच्ची किरत की मौके पर ही मौत हो गई। किरत, जो इंदरजीत सिंह की बेटी थी, आदमपुर के उदेसियां गांव की रहने वाली थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्ची रोजाना की तरह सुबह स्कूल बस से स्कूल पहुंची थी। जब बस स्कूल गेट पर रुकी और उसे उतारा गया, तभी वह बस के पिछले टायर की चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि ज़ाइवर ने बच्ची के उतरने के बाद तुरंत बस आगे बढ़ा दी, जिससे यह हादसा हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही थाना आदमपुर की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल, जालंधर में पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर

लिया है। ज़ाइवर को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि बस को भी जब्त कर लिया गया है। घटना के बाद परिजनों में रोष फैल गया और उन्होंने जालंधर—होशियारपुर हाईवे को आदमपुर के पास जाम कर दिया, जिससे यातायात में भारी बाधा उत्पन्न हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर शांत करवाने का प्रयास किया। पुलिस का कहना है कि स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली जाएगी। साथ ही, ज़ाइवर का मेडिकल भी करवाया जाएगा और यदि वह नशे की हालत में पाया गया, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूल प्रशासन और बस स्टाफ की लापरवाही की पूरी जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस स्कूल में 300 से अधिक छात्र पढ़ते हैं, ऐसे में सुरक्षा मानकों की अनदेखी भविष्य में और भी गंभीर घटनाओं को जन्म दे सकती है।

जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, पंजाब से एसवाईएल का पानी लेकर रहेंगे : अभय चौटाला

कुरुक्षेत्र ११/०१ (संवाददाता): इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने शनिवार को कहा कि राज्य में इनेलो की सरकार बनने पर पंजाब सतलुज यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) का पानी लेकर रहेंगे। चौटाला ने कहा कि हमने केवल एसवाईएल की लड़ाई नहीं लड़ी, हमने चाहे कांग्रेस की सरकार थी, या अब भाजपा की सरकार है, हमेशा सरकार के गलत फैसलों का डटकर विरोध किया है। एसवाईएल के

लिए हमने उच्चतम न्यायालय तक लड़ाई लड़ी और जीत कर आये।" उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आज उच्चतम न्यायालय में जाने के बजाय बैठक करके उस मामले को उलझाना चाहती है। उन्होंने कहा," पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ इस मुद्दे पर बात करने की जरूरत नहीं है। न्यायालय का फैसला हरियाणा के पक्ष में आ चुका है, उसे लागू करवाया जाना चाहिए। अगर पंजाब सरकार उच्चतम न्यायालय का फैसला नहीं मानती है, तो

अवमानना का नोटिस दो। अपने आप सुप्रीम कोर्ट सख्त निर्णय लेगी।" चौटाला ने कहा, "एसवाईएल के लिए हम कोई भीख थोड़े मांग रहे हैं, ये हमारा हिस्सा है। शाह आयोग की रिपोर्ट को लागू करना पड़ेगा। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी एसवाईएल का पानी पंजाब के गले में अंगूठा डाल कर लेंगे।" कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) पेपर की तारीख के संबंध में चौटाला ने कहा कि हमने सरकार को लिखा है कि तारीख गलत तय की है,

इसको आगे किया जाये। 27 तारीख को तीज का दिन है। हरियाणा का बड़ा पर्व है। खाद की किल्लत पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि खाद पोर्टल पर मिलेगी, जो सही नहीं है।" उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी छोड़कर गए लोग 25 सितंबर को चौ. देवीलाल के जन्मदिवस पर वापस पार्टी में शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी के अलग होने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आम आदमी

पार्टी से आम आदमी किनारा करेगा। हरियाणा में आम आदमी ने इनसे किनारा कर लिया, अब पंजाब में भी कर लेगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां पंजाब में एसवाईएल के मुद्दे पर एक हो जाती हैं और हरियाणा में उनका विरोध करती हैं। आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल खुद को हरियाणा का बेटा बताते हैं, मगर पानी नहीं देते है। हरियाणा के लिए आम आदमी पार्टी सबसे घातक पार्टी है।

रंजिश या प्रेम प्रसंग! महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या

हिसार ११/०१ (संवाददाता): हरियाणा में हिसार जिले के हांसी में शुक्रवार रात महिला की हत्या कर दी गयी। घटना का पता तब लगा जब मृतका की मां ने सुबह उठकर देखा तो वह बिस्तर पर नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने घर में देखा फिर वह छत पर गयी तो देखा उनकी बेटी कविता का शव खून से लथपथ पड़ा मिला।



उसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी। घटना की सूचना

मिलने पर पुलिस उपाध्ीक्षक विनोद शंकर और पुलिस बल मौके पर

पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर हांसी के नागरिक हॉस्पिटल में पहुंचाया। शंकर ने कहा कि उन्हें सुबह सात बजे घटना की सूचना मिली थी। इसके बाद टीम यहां पहुंची और देखा कि महिला की पत्थर मारकर हत्या की गयी है। मां से पूछताछ हुई है, जिसमें उन्होंने बताया कि रात में घर का दरवाजा अंदर से बंद था। बेटी उनके पास ही सोई

हुई थी, वह छत पर कैसे गई और अंदर कौन आया, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। फिलहाल, पुलिस रंजिश और प्रेम प्रसंग को जोड़कर मामले की जांच कर रही है। मृतक कविता का शव हांसी के पोस्टमार्टम कक्ष में रखा हुआ है। परिजनों के बयान दर्ज होने के बाद पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपेगी।

रोहतक मंथली प्रकरण : एडीजीपी के गनर सुशील कुमार के खिलाफ चार्जशीट तैयार, सात अक्तूबर को किया गया था गिरफ्तार

रोहतक ११/०१ (संवाददाता): मंथली प्रकरण में विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने एडीजीपी वार्ड पूरण कुमार के गनर सुशील कुमार के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली है। जल्द अदालत में दाखिल की जा सकती है।

शराब ठेकेदारी का काम करता हूँ। उसे बड़े बदमाशों जबरन वसूली के लिए जान से मारने की धमकी दी हुई है। इस कारण उसे पुलिस सुरक्षा मिली हुई है। हिमांशु भाऊ गैंग के कई साथियों ने शराब के ठेको में हिस्सा डाला हुआ है।

इस कारण अब जान का खतरा बना रहता है। उसे एक पुलिस कर्मचारी जिसने अपना नाम सुशील बतलाया। बोला आईजी आफिस में मिलने के लिए बुलाया गया है। साथ ही खुद को आईजी

का खास आदमी बताया। वह जून माह में आईजी आफिस गया तो वहां पुलिसकर्मी सुशील कुमार ने मुझसे धमकी भरे लहजे में बात की। कहा की अगर रोहतक में शराब का काम करना है तो मंथली देनी पड़ेगी। नहीं तो दूसरे बदमाशों और ठेकेदारों के साथ तुम पर शराब तस्करी के मुकदमे दर्ज करवा देंगे। फिर एक दिन उसका फोन आया की वह काम करना है। उसने लोकेशन भेजकर अपने सेक्टर—एक स्थित कार्यालय में बुलाया। उसने

अपने एक साथी जयभगवान को भी बुला लिया। पुलिसकर्मी सुशील ने मंथली के तौर पर ढाई लाख रुपये मांगे। कहा कि आईजी साहब पूरी सपोर्ट करेंगे। पुलिस ने आरोपी सुशील कुमार को एफआईआर दर्ज कर सात अक्तूबर को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से आरोपी न्यायिक हिरासत के कारण जेल में बंद हैं। रोहतक जेल से उसे अंबाला जेल भेजा जा चुका है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि एसआईटी ने आरोपी सुशील कुमार के

खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली है। अदालत में दाखिल करने से पहले उसे कानूनी एक्सपर्ट की राय ली जा रही है। ताकि कोई कमी न रह जाए। उम्मीद है शुक्रवार शाम तक जांच टीम अदालत में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अभी अदालत में कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। दाखिल करने के लिए चार्जशीट तैयार की जा रही है। जल्द दाखिल किया जाएगा।

वहीं, मंदिर परिसर के आसपास कुछ नई दरारें देखी गई हैं। ऐसे में अब घाटी के लोगों को भी डर सताने लगा है कि कहीं कोई बड़ी आपदा तो नहीं आने वाली है। पिछले कई सालों से बिजली महादेव रोपवे को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं, भगवान बिजली महादेव ने गुर देवता के माध्यम से कहा है कि बिजली महादेव में रोपवे नहीं बनना चाहिए, लेकिन कुछ नेता अपनी जिद के कारण बिजली महादेव में रोपवे बनाने में लगे हुए हैं।

अवैध एमटीपी किट हुई बरामद

रेवाड़ी। रेवाड़ी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेलेवे स्टेशन पर बने एक मेडिकल स्टोर पर अवैध ा रूप से बेची जा रही एमटीपी किट बरामद की हैं। ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर ने कंपनी के मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है। जांच में स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को यहां से सेल—परचेज बिल नहीं मिले। दरअसल, रेवाड़ी के रेलेवे स्टेशन पर दवा दोस्त कंपनी का मेडिकल स्टोर चल रहा है।



अमा बस दुर्घटना: सीएम ने 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की

भुवनेश्वर ११/०१ (संवाददाता): ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने रविवार को चुनिंदा शहरी क्षेत्रों में चलने वाली राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा %अमा बस% की टक्कर में एक ऑटो-रिज्शा चालक की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री माझी ने राज्य परिवहन विभाग को राजधानी क्षेत्र शहरी परिवहन (सीआर यूटी) के समन्वय से अमा बस सेवाओं से जुड़ी दुर्घटनाओं को रोकने और समग्र सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए प्रभावी उपाय करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। उन्होंने दुर्घटना



में घायल छात्रा के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। %अमा बस% सेवाओं से जुड़ी बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को सीआरयूटी के समन्वय से इस समस्या के समाधान और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए प्रभावी उपाय करने का निर्देश

दिया।

अमा बस चालकों के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ऐसे प्रशिक्षण में न केवल ड्राइविंग कौशल पर बल्कि चालकों के शारीरिक

और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने चालकों में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के उद्देश्य से मॉड्यूल शामिल करने का भी सुझाव दिया।

मुख्यमंत्री ने मोटर वाहन निरीक्षकों (एमवीआई) को अमा बस वाहनों की नियमित

फिटनेस जांच करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने वाणिज्य और परिवहन विभाग को व्यवस्थित बस फिटनेस निरीक्षण करने के लिए एक समर्पित दल गठित करने का निर्देश दिया। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने वाणिज्य और परिवहन विभाग को नियमित समीक्षा करने और समग्र स्थिति में ठोस सुधार लाने के लिए निरंतर कदम उठाने की सलाह दी।

गौरतलब है कि शनिवार दोपहर रूपाली स्कायर ट्रेफिक जंक्शन पर तेज रज्जार से आ रही अमा बस ने रेड सिग्नल पर रुकी एक ऑटो-रिज्शा को कुचल दिया, जिससे ऑटो-रिज्शा ड्राइवर बिष्णु पात्रा (60) की मृत्यु हो गई और एक छात्रा सहित तीन यात्री घायल हो गए।

हाथियों के द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाने से किसानों की नौद हाराम

राउरकेला ११/०१ (संवाददाता): सुंदरगढ़ जिले के लाठीकटा तथा सबडेगा ज़िलों में 81 हाथियों के झुंड ने आतंक मचा रखा है। हाथियों के द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाने से किसानों की नौद हाराम हो गई है। वन विभाग की ओर से इन्हें खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। लाठीकटा ज़िलों में 41 हाथियों के होने से बुचा हांडाए डाइटोलाए रेलपोषए बिरुआल क्षेत्र के लोग हाथियों से आतंकित हैं। सबडेगा ज़िलों में 40 हाथियों का झुंड है। वन विभाग की ओर से हाथियों पर नजर रखने के साथ ही गांवों की ओर उन्हें आने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लाठीकटा ज़िलों के बीरकेरा पंचायत क्षेत्र में तीन दिन से 41 हाथियों के झुंड देखा जा रहा है। इनके झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के जंगल से इस ओर आने का अनुमान लगाया जा रहा है।

जगन्नाथ मंदिर में नए लाइन सिस्टम को लेकर सेवादारों और सुरक्षाकर्मियों में झड़प, दर्शन में रुकावट

भुवनेश्वर ११/०१ (संवाददाता): पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए नई लाइन व्यवस्था को लेकर मंदिर के सेवकों और सुरक्षाकर्मियों के बीच मतभेद के बाद तनाव बढ़ गया। यह मुद्दा साटा पहाचा के पास उठा, जो मंदिर के अंदर दर्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले मुख्य रास्तों में से एक है। सेवकों ने नए फेंसले पर आपत्ति जताई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि श्रीमंदिर में तैनात स्पेशल सिज्योरिटी फोर्स ने साटा पहाचा के नीचे सिंगल-लाइन लाइन सिस्टम शुरू किया। खबर है कि यह कदम मंदिर के सेवकों से पहले से बातचीत किए बिना लागू किया गया। सेवकों ने इस बदलाव पर कड़ा विरोध जताया, उनका कहना था कि यह मंदिर के पुराने रीति-रिवाजों और दर्शन के तय तरीकों के खिलाफ है। हाथापाई



से थोड़ी देर के लिए अफरा-तफरी यह असहमति जल्द ही दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस में बदल गई। चश्मदीदों ने बताया कि बहस बढ़ने पर इलाके में धक्का-मुक्की हुई, जिससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई और उस समय मौजूद भक्तों को परेशानी हुई। साटा पहाचा से दर्शन रोकें गए विरोध जताने के लिए, सेवकों

ने साटा पहाचा रास्ते से दर्शन रोक दिए। इस फेंसले से मंदिर के उस हिस्से में आना-जाना रुक गया। सेवादारों का कहना था कि दर्शन के इंतज़ाम में कोई भी बदलाव मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन और मंदिर के रीति-रिवाजों के लिए पारंपरिक रूप से जिम्मेदार लोगों से सलाह-मशविरा करके किया जाना चाहिए। अफसरों ने

व्यवस्था ठीक करने के लिए कदम उठाया मंदिर के अधिकारियों ने बाद में हालात को शांत करने के लिए दखल दिया और सेवादारों और सुरक्षाकर्मियों दोनों से बातचीत शुरू की।

हालात नॉर्मल करने की कोशिश की गई, जबकि भक्तों से गुज़ारिश की गई कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, वे दूसरे इंतज़ामों में मदद करें।

माझी ने ओपीएससी को राज्य सिविल सेवा परीक्षा में 151 पद भरने का निर्देश दिया

भुवनेश्वर ११/०१ (संवाददाता): मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन (ओपीएस सी) से राज्य सिविल सर्विस में 14 समेत 151 और खाली पोस्ट भरने के लिए एग्जाम कराने की सिफारिश की। मुख्यमंत्री का यह निर्देश ओपीएससी के 31 दिसंबर के नोटिफिकेशन पर बड़े पैमाने पर नाराजगी के बाद आया है, जिसमें हफ, हक्सर और ओडिशा रेवेन्यू सर्विस को छोड़कर सात सर्विस में 314 खाली पोस्ट भरने की बात कही गई थी। ओपीएससी ने ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इन 314 पोस्ट में सात सर्विस में खाली पोस्ट शामिल थीं, जिनमें से 104 पोस्ट महिलाओं के लिए रिज़र्व थीं। अकेली रूथ, सर्विस, ओडिशा पुलिस सर्विस (ओपीएस) में 12 खाली पोस्ट हैं। ओडिशा टैक्सेशन एंड अकाउंट्स सर्विस और ओडिशा लेबर सर्विस जैसी रूथ क्सर्विस में एक के बाद



एक 176 और 98 पोस्ट खाली हैं, जबकि ओडिशा स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सर्विस, ओडिशा टूरिज्म सर्विस, ओडिशा एक्ससाइज सर्विस और ओडिशा कोऑपरेटिव सर्विस में एक के बाद एक 10, आठ, छह और चार खाली पोस्ट हैं। सीएमओ की तरफ से जारी एक ऑफिशियल रिलीज में कहा गया, हालांकि, नौकरी चाहने वालों के गुस्से को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने दखल दिया और इन सभी पोस्ट का रिव्यू किया और खाली पोस्ट भरने का निर्देश दिया। ओपीएससी से OAS में 14 पोस्ट, ओडिशा रेवेन्यू सर्विस में 113, ओडिशा ट्रांसपोर्ट सर्विस (हक्सर) में 16

और ओडिशा वेलफेयर सर्विस में 8 पोस्ट भरने का अनुरोध किया गया है। इसमें कहा गया है कि कुल 151 और पोस्ट की सिफारिश की गई है। सीएमओ ने कहा कि मुख्यमंत्री को सिफारिश से इन पोस्ट के लिए इच्छुक कई युवाओं को मदद मिलेगी। माझी ने कहा कि राज्य सरकार रोजगार सेक्टर को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रही है, और पिछले 18 महीनों में लगभग 40,000 सरकारी पोस्ट भरी गई हैं। मुख्यमंत्री ने सभी डिपार्टमेंट को सरकारी सेक्टर में खाली सभी पोस्ट भरने के लिए कमीशन को सिफारिश करने का भी निर्देश दिया है।

राउरकेला ११/०१ (संवाददाता): राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) के निदेशक प्रभारी (डीआईसी), श्री आलोक वर्मा ने नए साल 2026 के मौके पर आरएसपी के कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा सुधार का हर छोटा कदम संगठन के समग्र प्रदर्शन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।

2025 कैलेंडर वर्ष के दौरान आरएसपी के सभी लोगों के परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए, डीआईसी ने आगे कहा, हमारे कर्मचारियों ने सभी विभागों में जो समर्पण, टीम वर्क और मुश्किलों का सामना करने की क्षमता दिखाई है, वह सच में तारीफ के काबिल है। मैं सभी को उत्पादकता बढ़ाने और तकनीकी-अर्थशास्त्र को और बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। सामूहिक प्रतिबद्धता और केंद्रित निष्पादन के साथ, हम 2029 तक आरएसपी को



सबसे कम लागत वाला स्टील उत्पादक बनाने के अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ सकते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी, श्री आलोक वर्मा ने कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन), श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निदेशक (खान विकास एवं सीएमएलओ), श्री बी के गिरि, कार्यपालक निदेशक (वर्क्स), श्री विश्व रंजन पलाई, कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन), श्री अनिल

आरएसपी में सर्वाधिक 'नीयर-मिस' मामलों की रिपोर्टिंग करने वाले विभाग समानित



राउरकेला ११/०१ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के जिन विभागों ने चालू वित्तीय वर्ष की तृतीय त्रिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2025) के दौरान सर्वाधिक 'नीयर-मिस' यानि बाल-बाल बचने वाले मामलों की रिपोर्टिंग की थी उन्हें, 2 जनवरी 2026 को मंथन समेलन कक्ष में आयोजित सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान निदेशक-प्रभारी, श्री आलोक वर्मा द्वारा सज्जानित किया गया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक (खान विकास), श्री बी के गिरी, कार्यपालक निदेशक (संकार्य), श्री बी. आर. पलाई, कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन), श्री अनिल कुमार, कार्यपालक

निदेशक (खान), श्री एम पी सिंह, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी (विज्ञ), श्री राजेश दासगुप्ता सहित कई मुख्य महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 'नीयर-मिस' मामलों की रिपोर्टिंग सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मापदंड मानी जाती है। 569 मामलों की रिपोर्टिंग के साथ स्टील मेल्टिंग शांप-1 ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। मुख्य महाप्रबंधक (एसएमएस-1), श्री सुनील बी कार्था ने अपनी टीम के साथ पुरस्कार ग्रहण किया। 273 मामलों के साथ हॉट स्ट्रिप मिल-2 ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जिसके लिए मुख्य महाप्रबंधक (हॉट स्ट्रिप मिल्स एवं ऑक्जिलरीज), श्री सुब्रत कुमार एवं उनकी टीम

को सज्जानित किया गया। न्यू प्लेट मिल ने 188 'नीयर-मिस' मामलों की रिपोर्टिंग के साथ तृतीय स्थान पर रहा। मुख्य महाप्रबंधक (एनपीएम, एसपीपी एवं डिजिटलीकरण), श्री आर के मुदुली ने अपनी टीम के साथ पुरस्कार प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन मुख्य महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं), श्री हीरालाल महापात्र, तथा महाप्रबंधक (सुरक्षा अभियांत्रिकी), श्री अबकाश बेहरा द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि, वर्ष 2025 के दौरान कुल 4661 'नीयर-मिस' मामलों की रिपोर्टिंग की गई, जो वर्ष 2024 में रिपोर्ट किए गए 1691 मामलों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है।

कांग्रेस ने स्पीकर से कोटा पर प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया



भुवनेश्वर ११/०१ (संवाददाता): ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को मांग की कि राज्य सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों, जिसमें टेक्निकल और मेडिकल कोर्स शामिल हैं, और सरकारी नौकरियों में ST, SC और OBC को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक प्रस्ताव लाएं और उसे विधानसभा में पास करें।

OPCC अध्यक्ष भक्त चरण दास, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जेना और कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कदम सहित

कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में विधानसभा में स्पीकर सुरमा पाढ़ी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि स्त्र, स्त्र और हृष्ट राज्य की आबादी का लगभग 94 प्रतिशत हैं (54 प्रतिशत OBC और लगभग 40 प्रतिशत SC और

ST), लेकिन उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया है।

इसमें आगे कहा गया है कि इस संबंध में एक प्रस्ताव सदन के मौजूदा सत्र में सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए और मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा जाना चाहिए।

सुधार का हर छोटा कदम संगठन के समग्र प्रदर्शन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है-आलोक वर्मा

इस मौके को यादगार बनाने के लिए ज्ञानार्जन एवं बिकास केंद्र में औपचारिक केक भी काटे गए।

विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के साथ बातचीत करते हुए निदेशक प्रभारी ने आर.एस.पी. कर्मसमूह को विभिन्न उपलब्धियों के लिए बधाई दी और एक एकीकृत इस्पात संयंत्र की उत्पादन श्रृंखला में प्रत्येक विभाग के महत्व पर जोर दिया और बताया कि कैसे प्रत्येक इकाई संयंत्र की सफलता में अपने तरीके से योगदान दे सकती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2026 पिछले वर्ष से भी बेहतर होगा और आर.एस.पी. उत्पादन में उत्कृष्टता के नए शिखर को छूएगा।

कर्मचारियों ने अपनी ओर से संगठन के उद्यमिता के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक सभी प्रकार से सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।